संवाददाता सम्मेलन में जारी प्रेस रिलीज

'राहत वितरण की प्रक्रियाओं में जातिय समीकरण हावी' - दलित वॉच

बिहार में कोसी नदी के तटबन्ध के टूटने की वजह से आए भीषण बाढ़ से प्रभावित दलित समुदायों की स्थितियों की निगरानी के लिए कई संस्थाओं के नेटवर्क 'दलित वॉच' के 105 स्वेच्छासेवकों द्वारा पिछले दो सप्ताहों के दौरान पाँच जिलों में स्थापित 204 राहत शिविरों की सघन निगरानी की गई। ज्ञातव्य है कि 'दलित वॉच' का गठन 2007 के बाढ़ के बाद किया गया था, ताकि राहत व पुनर्वास की प्रक्रियाओं के दौरान दलितों के खिलाफ होने वाले भेदभाव व बहिष्करण की सम्भावित घटनाओं पर नज़र रखी जा सके तथा पीड़ितों को उनका अधिकार दिलवाने में मदद की जा सके। इस नेटवर्क में राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान, नारी गुंजन, बचपन बचाओ आन्दोलन, लोकशक्ति संगठन, दलित समन्वय, बाढ़ सुखाड़ मुक्ति आन्दोलन व प्रैक्सिस जैसी संस्थाएँ व संगठन शामिल हैं।

निगरानी की प्रक्रियाओं के दौरान एक ओर जहाँ राहत सामग्रियों व व्यवस्थाओं की चरम अपर्याप्तता के अनेक उदाहरण दिखे, वहीं जातिय समीकरणों की वजह से उपलब्ध सीमित संसाधनों का विशेष रूप से वंचित दलित समुदायों तक न पहुँच पाने व उनके प्रति दुर्व्यवहार की भी अनेक घटनाएँ दिखीं। उदाहरण के लिए, सुपौल जिले के प्रतापगंज प्रखण्ड के बाँसचौक शिविर में चमार समुदाय के श्री भोकूराम को भोजन वितरण के दौरान अपने बच्चे के लिए भोजन की मांग करने पर दबंग जाति के सुरक्षाकर्मियों के हाथों मारपीट का शिकार होना पड़ा। मधेपुरा के शंकरपुर प्रखण्ड के मौरा भारती गाँव में चल रहे शिविर में दलित परिवारों को सिर्फ माड़भात व नमक दिया गया जबकि इसी शिविर में रह रहे दबंग समुदाय के लोगों को दाल भात के साथ सब्जी भी दी गई। इसी जिले के शिविर संख्या 43 में रह रही मुसहर जाति की सोनी कुमारी को चापाकल के इस्तेमाल के दौरान छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा व शिकायत करने पर मारपीट का भी शिकार होना पड़ा। मधेपुरा के ही बिहारीगंज इलाके के गायत्री झावर कन्या मध्य विद्यालय में चल रहे शिविर में एक गर्भवती महिला के प्रसव के लिए 700 रू0 लिए गए। पूर्णिया के मुरलीगंज प्रखण्ड के रजनी गाँव के शिविर को, जहां बडी संख्या में मुसहर जाति के लोग शरण लिए हुए थे, को असमय समाप्त कर दिया गया। सहरसा के बुआरी व सिंघियान गाँवों में चल रहे शिविरों में दबंग जाति के लोगों को स्कूल के बरामदे में खाना परोसा जाता है जबकि दलित जाति के लोगों को मैदान में। अररिया जिले के नरपतगंज प्रखण्ड के फतेहपुर मध्य विद्यालय में चल रहे शिविर में मुसहर जाति के दुखी सदा को बीमारी की हालत में इलाज की सुविधा हासिल करने से रोका गया, जिनकी बाद में मौत हो गई। इसी जिले के वार्ड संख्या 8 में चल रहे शिविर में दलित समुदाय के मृतकों का ब्यौरा लेने से मना कर दिया गया, जबकि पघराहा के कन्या मध्य विद्यालय में चल रहे शिविर में दबंग जाति के लोगों को भोजन परोसे जाने के बाद दलितों को भोजन दिया जाता है। नरपतगंज के ही जनता उच्च विद्यालय में रह रही 14 साल की एक दलित बच्ची के साथ शौच के लिए जाने के दौरान बलात्कार का शिकार होना पड़ा। मधेपुरा जिले के शंकरपुर प्रखण्ड के कवियाही व सोनबरसा गाँवों के पास शरण लिए दलित परिवारों तक राहत की सामग्रियाँ पहुँचने से पहले ही अन्य दबंग जातियों के लोगों द्वारा लूट ली गई। सहरसा जिले के सौरबाजार मध्य विद्यालय में चल रहे शिविर में दुसाध जाति के नंदकिशोर पासवान से दबंग जाति के लोगों ने 2200 रू0 लूट लिए। ऐसी ही बात सुपौल जिले के बसन्तपुर प्रखण्ड के सीतापुर के शिविर में हुई जहाँ के लिए आवंटित 30 चापाकलों को दबंग जाति के लोगों ने सडक पर ही लूट लिया। सभी जिलों में राहत वितरण की प्रक्रियाओं के प्रबन्धन में नगन्य संख्या में दलित समुदाय के सदस्यों को शामिल किया गया है।

इस आकलन के मद्देनज़र दलित वॉच दलित समुदाय के बाढ़ प्रभावित लोगों की अविलम्ब पहचान व क्षतियों की पंजीकरण की मांग करती है, तथा उनके लिए दो समय के पर्याप्त

भोजन, आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएँ, स्वच्छता सुविधाएँ, आवासीय सुविधाएँ, महिला चिकित्सकों व परिचारिकाओं की उपलब्धता, प्रबन्धन समितियों में दलित समुदाय के लोगों की भागीदारी व विशेष रूप से बदहाल लोगों के लिए प्राथमिकता के साथ सेवाओं व सुविधाओं की उपलब्धता के सुनिश्चित किए जाने की मांग करती है। साथ ही, यह दलित समुदाय के लोगों के द्वारा अनुभव किये गए भेदभाव, बहिष्करण व अत्याचार की घटनाओं के खिलाफ 1989 के अ0जा0/अ0ज0जा0 अत्याचार निवारक कानून के तहत त्वरित कारवाई, तथा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की मांग करती है।

आने वाले दिनों में 'दलित वॉच' बाढ़ से प्रभावित दलित समुदायों द्वारा झेले गए नुक्सानों तथा उनके पुनर्वास की ज़रूरतों का आकलन करेगी। साथ ही, आने वाले दिनों में दलित वॉच आपदा राहत कोष के प्रावधानों के अनुसार दलितों के अधिकारों को हासिल करने की दिशा में अभियान चलाएगी।

***